श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पाइप-लाइन जुलाई, 1989 में पूरी होनी थी, पूरी होगी । उसमें कोई डिले नहीं होगा और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि कोस्ट बढ़ जाएगी । फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में जो गुना का फर्टिलाइजर प्लाट है, जहां तक हमारी पाइप-लाइन बन गयी है, उन्होंने थोड़ी गैस लेना शुरू किया है और एक-दो महीने में वे पूरी गैस लेंगे । आवला का फर्टिलाइजर प्लाट और जगदीशपुर का प्लांट, यह आ जाएगा तो फिर समय पर पूरी गैस वहां मिल जाएगी । शाहजहांपुर और बबराला के बारे में थोड़ी दिक्कत है, उसमें काम शुरू होने में थोड़ी देर होती है, जहां तक उनके प्रस्ताव का है, वह अभी भी है, अपनी जगह पर है, देरी उसमें जरूर होगी । लेकिन यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि अगर देरी होती है तो हम उस गैस का उपयोग क्या करें, कैसे करें ? हम चाहेंगे कि जो पूंजी उसमें लगी है, उसका उपयोग हो, इस पर पूरा सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसे उपभोक्ताओं की खोज कर रहे हैं, जो इस बीच में ले सकें, हम पावर डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं, और लोगों से भी बात कर रहे हैं । तो इस तरह से इसके अधिकतम उपयोग को और जो पूंजी लगी है, उसके उपयोग को, ससाधनों के उपयोग को हम सुनिश्चित कर रहे हैं । जो आपका मूल प्रश्न है, उसमें मैं पूरी तरह आशान्वित हूं कि न इसमें देर होगी और न कीमत बढ़ेगी ।

श्री शंकर सिंह वाघेला सर, गैस के लिए अलग ओ एन. जी. सी. को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आयल से जो बाय-प्रोडक्ट होता है तो इस डिले से जो फर्टिलाइजर प्लांट का मामला है, इससे गैस अथोरिटी आफ इण्डिया को कितना नुकसान होगा और क्या भारत सरकार की ऐसी नीति है कि जहां गैस फ्लेअर-अप हो रही है करोड़ों रुपयों की, वहां ही ऐसे गैस-बेस्ड प्लांटस इम्पोज हों, वहां ही गैस का प्रोडक्शन बिजली के लिए हो, जहां-जहां गैस फ्लेअर-अप हो रही है, उसके उपयोग के ऐसे कोई परपोजल गुजरात राज्य से या दूसरे राज्यों से मिले हैं ? क्या वे एज-अर्ली-एज पोसिबल नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए देंगे या नहीं देंगे ? और अगर नहीं देते हैं तो कितना नुकसान गैस अथोरिटी आफ इण्डिया को होता है ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, अगर एक गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट में देरी होती है तो गैस अथोरिटी को कीमत में प्रतिदिन 37 लाख रुपए का नुकसान होता है और अगर पावर प्लांट को देरी होती है तो करीब 45 लाख रुपए का नुकसान होता है । इसलिए मैंने निवेदन किया कि पूरी तरह से हम इस पर विचार कर रहे हैं । दो तरह की गैस होती है, एक तो तेल के साथ निकलती है, दो तरह की गैस होती है । एक फ्री गैस होती है और फ्री गैस को हम रिजर्व रख सकते हैं और एसोसिएटेड गैस को निकालना पड़ता है । हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को ढूंढ लें जो इस बीच में गैस को ले लेंगे । फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है । सारा प्रश्न विचाराधीन है । और अगर हम यह सोचें कि जहां गैस जलायी जाती है वहीं फर्टिलाइजर प्लाट लगाए तो बाम्बे हाई में जाकर लगानी पड़ेगी । जहां तक गुजरात का सवाल है . . .

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Inadequate Compensation to the Tribals of Hazaribagh Area

121 SHRI SUKOMAL SEN :

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tribals of Hazaribagh area were not paid adequate compensation for their lands, which were leased to the West Bokaro Colliery despite the fact that Colliery is earning a huge profit from the area;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to protect the interest of the tribals ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE) : (a) to (c) West Bokaro Colliery is a privately-owned, captive

mine of the TISCO It is not in the public sector. Central Government does not, therefore, directly come into the picture in this regard.

Accordingly to our information, altogether 108.91 acres of Raiyyati land has been recently acquired by West Bokaro Colliery under the Land Acquisition Act for mining and allied purposes. Of the above land, only 23 57 acres belong to the tribal families, numbering 5 in all. The compensation for the acquired land has been paid at the following rates .—

A **Dhan (Paddy) Land :**

(i) Dhan-I	Rs. 20,455/- per acre
(ii) Dhan-II	Rs 12,784/- per acre
(iii) Dhan-III	Rs 10,228/- per acre

B **Tand (Upper) Land :**

(i) Tand-I	Rs. 20,455/- per acre
(ii) Tand-II	Rs 5,114/- per acre
(iii) Tand-III	Rs 1,278/- per acre

Compensation for the acquired land is usually paid on the basis of the market value at the time of acquisition of the concerned land. Since the land was acquired under the Land Acquisition Act, through the aegis of the State Government, it is presumed that adequate compensation, as provided under the Act, must have been paid to the tribal families However, if any injustice has been done to the tribal land owners in the process of acquisition of their lands, remedial action will have to be taken through appropriate administrative or legal action for which the State Government has been addressed

Measures to increase PLF by DESU

*126. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that to meet the growing demand of power, the Delhi Electric Supply Undertaking has initiated a number of measures to increase its plant load factor;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) to what extent the crisis of power in the Capital is likely to be resolved thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) to (c) There is no power crisis in Delhi The measures taken to meet the growing demand of power in Delhi include augmentation of DESU's own generation. A programme to renovate the units at the Indraprastha thermal station is also under implementation. The plant load factor of the station has increased from 50.2% in 1983-84 to 67.2% in 1986-87 The growing demand for power in Delhi will also be met from increased supply from the Badarpur thermal station and DESU's share in the new capacity to be added in the Central sector in the Northern Region Assistance to the extent possible will also be provided to DESU from the Northern grid.

Wages paid to women workers employed by KVIC

*128 SHRI NIRMAL CHATTERJEE :
SHRIMATI KANAK MUKHERJEE :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the women employed directly by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) are not guaranteed the minimum wages paid to unskilled workers;

(b) if so, whether it is in accordance with the Government's policy or is attributable to the manipulations of the management of KVIC;

(c) whether Government propose to initiate criminal prosecutions against the erring personnel; and

(d) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J VENGAL RAO) : (a) to (d) The Khadi & Village Industries Commission extends only financial, technical and marketing support to the State Khadi &